

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राजस्थान में बाह्य सहायता प्राप्त संचालित परियोजनाएँ
2.	'त्रिशूल' युद्धाभ्यास : भारत की तीनों सेनाओं का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास
3.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों के नवनियुक्त कुलगुरु 2. जयपुर महानिदेशक (स्पेशल ऑपरेशन) का नया पद सृजित 3. हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान 4. पांडुलिपियों का डिजीटलीकरण 5. पद्मश्री प्रोफेसर डॉ. डी. के. भार्गव 6. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB), जयपुर के नए सचिव 7. उपभोक्ता फीडबैक सिस्टम शुरू करने वाला राजस्थान का प्रथम डिस्कॉम 8. IIT जोधपुर और आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड MoU
4.	ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS)
5.	कुरिंजी फूल
6.	वनस्पति तेल उत्पाद, उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) आदेश, 2011
7.	वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ समिति (UN-GGIM)
8.	मर्कोसुर (Mercosur)
9.	जापान की पहली महिला प्रधान मंत्री
10.	यूरोपीय संघ-भारत रणनीतिक एजेंडा
11.	सेविला फोरम ऑन डेब्ट
12.	ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान
13.	सारंडा वन
14.	आधार के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी संबद्ध योजना (SITAA)
15.	राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता: GST

--:1:--

Daily Current Affairs

Date : 27 October, 2025



16.	RBI का स्वर्ण भंडार
17.	रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (REER)
18.	राज्य खनन तत्परता सूचकांक (SMRI)
19.	स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट्स, 2025
20.	वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI), 2025
21.	वैश्विक वन संसाधन आकलन (GFRA) 2025 रिपोर्ट
22.	सुंदरबन जलीय कृषि मॉडल
23.	वीरता पुरस्कार
24.	कॉमनवेल्थ गेम्स (राष्ट्रमंडल खेल)



--:2:--

राजस्थान परिदृश्य

राजस्थान में बाह्य सहायता प्राप्त संचालित परियोजनाएँ

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) के सहयोग से राजस्थान में 'राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन' परियोजना का संचालन शुरू किया गया।



मुख्य बिन्दु:

- उद्देश्य :** इस परियोजना का उद्देश्य वनीकरण, वन संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी बहाली के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बेहतर बनाना है।
- वित्त पोषण :** इस परियोजना को जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) द्वारा ₹26,133 मिलियन (लगभग 1,473 करोड़ रुपये) के आधिकारिक विकास सहायता ऋण से वित्त पोषित किया गया है।

Daily Current Affairs

Date : 27 October, 2025



अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- वर्तमान में राजस्थान में कुल 14 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ संचालित है।

क्र.सं.	योजना	संस्था	विवरण
1.	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम RUIDP (चरण-III)	ADB (एशियन डवलपमेंट बैंक)	टोंक, गंगानगर, झुँझुनूँ, पाली, भीलवाड़ा में जलापूर्ति और सीवरेज कार्य। कुल 12 शहरों में कार्य प्रगति पर है।
2.	राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना (चरण-IV) ट्रांच- I	ADB	14 शहरों में - जलापूर्ति और सीवरेज कार्य। परियोजना अवधि - जनवरी, 2020 से नवंबर, 2028 तक 13 अन्य शहरों में सीवरेज, कीचड़ और सेप्टिक प्रबंधन।
3.	राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, ट्रांच- I	ADB	इस परियोजना के तहत 16 शहरों में बुनियादी ढांचे पर काम किया जा रहा है।
4.	राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश परियोजना, ट्रांच - II	ADB	-

--:4:--

Daily Current Affairs

Date : 27 October, 2025



5.	राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश परियोजना, ट्रांच - III	ADB	-
6.	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना चरण-2	AFD (Agence Française de Développement)	13 जिलों (पूर्वी राजस्थान) में प्राकृतिक वनों का सुदृढीकरण, विकास और संरक्षण का उपयोग कर सकते हैं।
7.	राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना (चरण-2)	JICA (जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी)	झुँझुनूँ और बाड़मेर में जल उपचार संयंत्रों और जलापूर्ति सुविधाओं का निर्माण।
8.	राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना	JICA	राजस्थान के सभी जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्वास और बहाली।
9.	मरू क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना (ट्रांच-I & II)	NDB (न्यू डेवलपमेंट बैंक)	70 प्रतिशत NDB एवं 30 प्रतिशत राज्य द्वारा वित्त पोषित लाभान्वित जिले: श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुँझुनूँ, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर।

--5--

Daily Current Affairs

Date : 27 October, 2025



10.	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना-द्वितीय	विश्व बैंक (WB) और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB)	WB + AIIB - 70 प्रतिशत राजस्थान सरकार - 30 प्रतिशत
11.	राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम - द्वितीय	WB	वित्तीय साझेदारी: <ul style="list-style-type: none">■ विश्व बैंक : 1779 करोड़ रुपये■ राज्य सरकार : 893 करोड़ रुपये■ निजी क्षेत्र : 323 करोड़ रुपये
12.	राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढीकरण की परियोजना	WB	<ul style="list-style-type: none">■ वित्तपोषण - विश्व बैंक + राज्य सरकार■ परियोजना अवधि - जुलाई, 2018 से मार्च, 2025 तक
13.	राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना - II	KFW जर्मनी	47 प्रतिशत KFW ऋण, 33 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान, 20 प्रतिशत राज्य की हिस्सेदारी
14.	राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन	JICA	राजस्थान के 19 जिलों में सतत् पारिस्थितिक प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना।

--6--

'त्रिशूल' युद्धाभ्यास : भारत की तीनों सेनाओं का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास

चर्चा में क्यों?

- 30 अक्टूबर, 2025 से जैसलमेर के पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज से 'त्रिशूल' युद्धाभ्यास की शुरुआत होगी।



मुख्य बिन्दु:

- अवधि :** 30 अक्टूबर से 10 नवम्बर, 2025
- क्षेत्र :** जैसलमेर के भारत-पाक सीमा से लेकर गुजरात के कच्छ (सर क्रीक) तक।
- प्रतिभागी :** थल-सेना, नौसेना और वायु-सेना के कुल 30,000 जवान संयुक्त रूप से भाग लेंगे। यह भारत की तीनों सेनाओं का अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास है।

उद्देश्य :

- तीनों सेनाओं का एक साथ तालमेल और यूनिफाइड ऑपरेशन, डीप-स्ट्राइक व मल्टी-डोमेन वॉरफेयर का अभ्यास।
- हालिया सीमागत घटनाओं (जैसे ऑपरेशन 'सिंदूर' के बाद ड्रोन व घुसपैठ जोखिम) के मद्देनजर क्षेत्रीय सुरक्षा क्षमता मजबूत करना।
- नए स्वदेशी हथियारों व हाई-टेक सिस्टम्स का फ़ील्ड-टेस्टिंग।

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों के नवनियुक्त कुलगुरु</p> <ul style="list-style-type: none">■ डॉ. विमल डूकवाल - कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।■ डॉ. वीरेंद्र सिंह - कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।■ प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह - श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।■ डॉ. प्रताप सिंह - महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर।■ प्रोफेसर पवन कुमार - जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।■ प्रोफेसर गोविंद सहाय - डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।■ प्रोफेसर निमित्त रंजन - राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
2.	<p>जयपुर महानिदेशक (स्पेशल ऑपरेशन) का नया पद सृजित</p> <ul style="list-style-type: none">■ हाल ही में, राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ के स्थान पर सचिन मित्तल को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया।■ साथ ही, जयपुर महानिदेशक (स्पेशल ऑपरेशन) का नया पद सृजित किया गया है, जिसका पहला महानिदेशक आनंद श्रीवास्तव को बनाया गया है।■ उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाए गए आतंकवाद निरोधक दस्ते को उग्रवाद निरोध दस्ता नाम दिया है, जिसकी जिम्मेदारी दिनेश एम. एन. को सौंपी गई।

3.

हरियाली राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान

- कार्यक्रम की शुरुआत : 7 अगस्त, 2024 (हरियाली तीज के अवसर पर)
- स्थान : करौली के सपोटरा से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा।
- इस कार्यक्रम की प्रेरणा प्रधानमंत्री की पहल 'एक पेड़ माँ के नाम अभियान' से मिली।
- लक्ष्य : आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाना।
- उपलब्धियाँ : वर्ष 2024-25 तक राज्य में 7 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं।
- वर्ष 2025 में 10 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके तहत 11.50 करोड़ पौधे लगाए गए।

4.

पांडुलिपियों का डिजीटलीकरण

- जयपुर स्थित राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा 15वीं से 18वीं सदी तक की पांडुलिपियों का डिजीटलीकरण का कार्य संपन्न किया जा रहा है।
- इससे पूर्व अकादमी द्वारा 'वेद संरक्षण योजना' के तहत अथर्ववेद और सामवेद की सम्पूर्ण संहिता की श्रव्य-दृश्य प्रस्तुति (रिकॉर्डिंग) का डिजीटलीकरण किया गया।
- इस परियोजना का उद्देश्य जन-कल्याण की भावना को जन-जन तक पहुंचाना और वेद पाठ की लुप्त होती परंपरा को संरक्षित करना है।
- ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 'ज्ञान भारतम् मिशन' की शुरुआत भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत की पहचान, दस्तावेज़ीकरण, संरक्षण, डिजीटलीकरण, संरक्षण और संवर्धन करने के उद्देश्य से की गई।

5.

पद्मश्री प्रोफेसर डॉ. डी. के. भार्गव

- हाल ही में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के 50वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर प्रोफेसर डी. के. भार्गव को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।
- उन्हें यह सम्मान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने प्रदान किया।
- प्रोफेसर डी.के. भार्गव प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, जिन्हें चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है।

6.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB), जयपुर के नए सचिव

- हाल ही में, राजस्थान सरकार द्वारा दिनेश कुमार शर्मा को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB), जयपुर का नया सचिव नियुक्त किया गया।
- साथ ही, गजेन्द्र सिंह राठौड़ को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर का सचिव नियुक्त किया गया।

7.

उपभोक्ता फीडबैक सिस्टम शुरू करने वाला राजस्थान का प्रथम डिस्कॉम

- हाल ही में, जयपुर डिस्कॉम ने 'बिजली मित्र एप' के माध्यम से उपभोक्ता फीडबैक सिस्टम की शुरुआत की।
- जयपुर डिस्कॉम उपभोक्ता फीडबैक सिस्टम शुरू करने वाला राजस्थान का प्रथम डिस्कॉम है।

8.

IIT जोधपुर और आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड MoU

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जोधपुर और आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने मानवरहित हवाई वाहनों (UAV) और डीप-टेक नवाचार पर संयुक्त शोध एवं विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- इस साझेदारी का उद्देश्य स्वदेशी ड्रोन और UAV इंजन बनाने के साथ-साथ रक्षा और नागरिक उपयोग के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास करना है।



ओरल रिहाइडेशन सॉल्यूशन (ORS)



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत आदेश द्वारा उन सभी पेय पदार्थों पर ORS शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों का पालन नहीं करते हैं।



मुख्य बिन्दु:

ORS

- ORS नमक और चीनी का एक घोल है, जिसे स्वच्छ पानी में घोलकर पिया जाता है। यह तेज दस्त, लू या किसी भी अन्य बीमारी से होने वाले निर्जलीकरण के इलाज में उपयोगी होता है।

ORS का निर्धारित फार्मूला (WHO और यूनिसेफ द्वारा स्वीकृत):

- सोडियम क्लोराइड: 2.6 ग्राम/लीटर
- ग्लूकोज, ऐन्हाइड्रस: 13.5 ग्राम/लीटर
- पोटेशियम क्लोराइड: 1.5 ग्राम/लीटर
- ट्राइस सोडियम साइट्रेट, डाइहाइड्रेट: 2.9 ग्राम/लीटर
- इसे सबसे पहले 1971 में भारतीय पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ दिलीप महालनोबिस द्वारा विकसित किया गया था।

कुरिंजी फूल

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में तमिलनाडु के गुडलूर पहाड़ियों में 8 वर्षों के बाद बैंगनी रंग के कुरिंजी फूल खिले हैं। गुडलूर को हाल ही में फॉरेस्ट रिजर्व अधिसूचित किया गया था।

मुख्य बिन्दु:

कुरिंजी फूल

- कुरिंजी पौधे जीवन में केवल एक बार ही खिलते हैं।
- अधिक प्रसिद्ध नीलकुरिंजी (स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना) अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई (1,300 मीटर से अधिक) पर हर 12 साल में एक बार खिलता है।
- **प्रमुख स्थान:** पश्चिमी घाट के शोला वन।

महत्व:

- कुरिंजी का खिलना वास्तव में स्वस्थ घास-भूमि का संकेत होता है, वहीं इनमें क्षरण होने पर फूल खिलने में व्यवधान देखा जाता है।
- यह फूल जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के सूचक के रूप में कार्य करता है।

वनस्पति तेल उत्पाद, उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) आदेश, 2011

चर्चा में क्यों?

- उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वनस्पति तेल उत्पाद, उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) आदेश, 2011 (VOPPA Order) में संशोधन किया।

मुख्य बिन्दु:

मुख्य संशोधन

- खाद्य तेल की प्रोसेसिंग से संबंधित श्रृंखला (जैसे- उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण आदि) से जुड़े सभी हितधारकों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- सभी पंजीकृत संस्थाओं को अपने मासिक उत्पादन और भंडार (स्टॉक) की जानकारी सरकार के निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

भारत का खाद्य तेल क्षेत्रक

- भारत खाद्य वनस्पति तेल के बाजार में दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राजील के बाद चौथे स्थान पर है।
- भारत विश्व के कुल तिलहन उत्पादन में लगभग 5-6% का योगदान देता है।
- भारत को अपनी खाद्य तेल की 57% जरूरत आयात के ज़रिए पूरी करनी पड़ती है।



अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ समिति (UN-GGIM)



चर्चा में क्यों?

- भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन की संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समिति (UN-GGIM-AP) का सह-अध्यक्ष चुना गया है।



मुख्य बिन्दु:

UN-GGIM-AP:

- यह UN-GGIM के तहत पांच क्षेत्रीय समितियों में से एक है।
- **स्थापना:** यह संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसे आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के तहत 2011 में वैश्विक भू-स्थानिक डेटा प्रबंधन को समन्वित करने के लिए स्थापित किया गया था।
- यह एक शीर्ष अंतर-सरकारी तंत्र है जो भू-स्थानिक सूचना नीति के संबंध में निर्णय लेने के लिए कार्य करता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों को भू-स्थानिक डेटा और तकनीकों के बेहतर उपयोग के माध्यम से हल करना है।

मर्कोसुर (Mercosur)


चर्चा में क्यों?

- भारत और ब्राजील ने भारत और मर्कोसर ब्लॉक के बीच मौजूदा प्रिफ़ेन्शियल ट्रेड अग्रीमेंट (PTA) के दायरे को बढ़ाने पर सहमति जताई है।

मुख्य बिन्दु:

- **शुरुआत:** 1991
- **मुख्यालय:** मॉंटेवीडियो (उरुग्वे)
- यह दक्षिण अमेरिकी देशों का ट्रेड ब्लॉक है, जो मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **सदस्य देश:** अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे।
- वेनेजुएला की सदस्यता निलंबित कर दी गयी है।
- **भूमिका:** यह कस्टम्स यूनियन के रूप में कार्य करता है। इसमें एक समान एक्सटर्नल टैरिफ होता है, जो क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को आसान बनाता है।

जापान की पहली महिला प्रधान मंत्री

-  चर्चा में क्यों?
- जापान ने 'साने ताकाइची' को देश की पहली महिला प्रधान मंत्री के रूप में चुना है।

 मुख्य बिन्दु:

भारतीय और जापानी राजनीतिक प्रणालियों के बीच समानताएं

- **लिखित संविधान:** भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, जबकि जापान का संविधान लघु है और इसमें अधिकतम 5000 शब्द ही हैं।
- **संसदीय लोकतंत्र:** दोनों ही संसदीय लोकतंत्र हैं, जिनमें प्रधान मंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है।
- **द्विसदनीय विधायिका:** जापान की राष्ट्रीय डाइट में हाउस ऑफ़ रेप्रेसेंटेटिव (निम्न सदन) और हाउस ऑफ़ काउंसिलर्स (उच्च सदन) होते हैं, जबकि भारत की संसद में लोक सभा और राज्य सभा होती है।

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights):

- जापान में अध्याय III (अनुच्छेद 10-40) समानता, स्वतंत्रता और मानव गरिमा की गारंटी देता है।
- भारत में भाग III (अनुच्छेद 12-35), 6 मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है।
- **अन्य समानताएं:** स्वतंत्र न्यायपालिका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संवैधानिक सर्वोच्चता आदि।

यूरोपीय संघ-भारत रणनीतिक एजेंडा

चर्चा में क्यों?

- यूरोपीय परिषद ने यूरोपीय संघ-भारत रणनीतिक एजेंडा को मंजूरी प्रदान की। इसमें भू-राजनीतिक संदर्भ में उभरते अवसरों, चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए प्राथमिकता वाले पांच स्तंभों की पहचान की गई है।

मुख्य बिन्दु:

प्राथमिकता वाले पांच स्तंभ

- **समृद्धि और संधारणीयता:** यह आर्थिक संवृद्धि, रोजगार सृजन, डीकार्बोनाइजेशन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और निवेश संरक्षण समझौते (IPA) को अंतिम रूप देना** इसके केंद्रीय लक्ष्य हैं।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों और डिजिटल अवसंरचना पर सहयोग को गहरा करने पर केंद्रित है।
- **सुरक्षा और रक्षा:** वैश्विक सुरक्षा संबंधी खतरों, भू-राजनीतिक तनावों और तकनीकी परिवर्तनों से निपटना। उदाहरण के लिए- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समन्वय स्थापित करना और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा देना।
- **कनेक्टिविटी और वैश्विक मुद्दे:** यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, वैश्विक गवर्नेंस और तीसरे देशों में सहयोग को मजबूत करेगा। जैसे- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) और ग्लोबल गेटवे जैसी पहलों को मजबूत करना।
- **सभी स्तंभों में सक्षमकर्ता:** यह सभी चार मुख्य स्तंभों को समर्थन देने के लिए कौशल गतिशीलता, ज्ञान विनिमय, व्यापार सहभागिता और संस्थागत सहयोग को सुगम बनाएगा।

Daily Current Affairs

Date : 27 October, 2025



भारत-यूरोपीय संघ संबंध

- **राजनयिक संबंध:** भारत 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। 2004 में संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया था।
- **द्विपक्षीय व्यापार:** भारत और यूरोपीय संघ के बीच वस्तुओं का व्यापार 2024 में 120 बिलियन यूरो तक पहुंच गया था। EU भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** अप्रैल 2000 और दिसंबर 2023 के बीच यूरोपीय संघ से संचयी FDI अंतर्वाह 107.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:18:--

सेविला फोरम ऑन डेब्ट

चर्चा में क्यों?

- सेविला फोरम ऑन डेब्ट लॉन्च किया गया। यह फोरम संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के 16वें सत्र (UNCTAD16) में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में व्याप्त ऋण संकट से निपटना है।

मुख्य बिन्दु:

सेविला फोरम ऑन डेब्ट

- इसका नेतृत्व स्पेन कर रहा है। इसे UNCTAD तथा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) का समर्थन प्राप्त है।
- यह फोरम ऋण संधारणीयता, प्रबंधन और नवोन्मेषी समाधानों पर सभी हितधारकों, ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और शैक्षणिक समुदाय को एक मंच पर लाएगा।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान

चर्चा में क्यों?

- CAQM ने पूरे NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-II को लागू किया। CAQM की GRAP पर उप-समिति ने NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की बिगड़ती स्थिति के कारण स्टेज-II के तहत निर्धारित उपायों को लागू करने का निर्देश दिया है।

मुख्य बिन्दु:

- GRAP-2 के तहत कोयला और लकड़ी के उपयोग पर रोक लगाई गई है। साथ ही, डीज़ल जनरेटर के चलाने पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें कुछ अपवाद हैं।

GRAP

- यह दिल्ली के AQI के स्तर पर आधारित एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है। इसे AQI स्तरों के आधार पर निम्नलिखित चार चरणों में बाँटा गया है-
 - स्टेज 1: खराब श्रेणी (AQI 201 से 300)
 - स्टेज 2: बहुत खराब श्रेणी (AQI 301 से 400)
 - स्टेज 3: गंभीर श्रेणी (AQI 401 से 450)
 - स्टेज 4: अति गंभीर श्रेणी (AQI 451 से अधिक)।
- दिल्ली-NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM), ग्रैप (GRAP) के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
- CAQM की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत की गई थी।

--:20:--

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI):

- सरकार ने इसे वर्ष 2014 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण के स्तर को मापना और इसके खतरों के बारे में जनता को जानकारी देना है।
- **AQI को छह श्रेणियों में बाँटा गया है:**
 - उत्तम: 0-50
 - संतोषजनक: 51-100
 - मध्यम रूप से प्रदूषित: 101-200
 - खराब: 201-300
 - बहुत खराब: 301-400
 - गंभीर: 401-500
- **AQI की गणना आठ प्रदूषकों के आधार पर की जाती है — PM10, PM2.5, NO₂, SO₂, CO, O₃, NH₃, और Pb (सीसा)।**

सारंडा वन

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सारंडा में एक नए वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित करने के लिए आदेश दिया।

मुख्य बिन्दु:

- यह झारखंड में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा साल वन है। साल वृक्ष एक प्रकार का नम पर्णपाती वृक्ष है।
- सारंडा का अर्थ 'सात सौ पहाड़ियों की भूमि' है।
- **जीव-जंतु:** यहां एंडेंजर्ड प्रजाति फ्लाइंग लिज़र्ड्स और हाथी के पर्यावास हैं।
- **वनस्पति:** साल, कुसुम, मशरूम, महुआ आदि।
- यहां प्राप्त लगभग 80% मानव आबादी- हो, मुंडा, उरांव और कुछ अन्य आदिम जनजातियों से संबंधित है।

महत्त्वपूर्ण योजनाएँ

आधार के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी संबद्ध योजना (SITAA)

चर्चा में क्यों?

- यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी संबद्ध योजना (SITAA) लॉन्च की है।

मुख्य बिन्दु:

- **SITAA:** स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विथ आधार।
- **उद्देश्य:** भारत के डिजिटल पहचान इकोसिस्टम को मजबूत करना और सुरक्षा संबंधी नए खतरों जैसे डीपफेक्स, स्पूफिंग, और प्रेजेंटेशन अटैक से निपटना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत UIDAI.

आर्थिक परिदृश्य

राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता: GST

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, वस्तु एवं सेवा कर (GST) में किए गए नवीनतम बदलावों के तहत GST प्रतिपूर्ति उपकरण को समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्यों की राजस्व हानि और राजकोषीय स्वायत्तता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

मुख्य बिन्दु:

- GST प्रतिपूर्ति उपकरण का उद्देश्य GST के लागू होने के बाद राज्यों को होने वाली राजस्व हानि के लिए मुआवजा प्रदान करना है।

राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता से संबंधित रुझान

- राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता का ह्रास:** GST ने कराधान संबंधी शक्तियों को राज्यों से GST परिषद को हस्तांतरित कर दिया है। जबकि GST परिषद में केंद्र का प्रभुत्व है।
- राजकोषीय असंतुलन:** कानून एवं व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विषयों पर प्रमुख जिम्मेदारियां राज्यों की होती हैं। GST के लागू होने के बाद से ज्यादातर कर वसूलने की शक्ति केंद्र के पास चली गई है। ऐसे में राज्यों के पास खर्च करने की जिम्मेदारी तो बनी रही, लेकिन राजस्व जुटाने की शक्ति कम हो गई। इससे राजकोषीय असंतुलन उत्पन्न हो रहा है।
- वित्तीय संसाधन आवंटन में घटती हिस्सेदारी:** सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा कम हो गया है।
- वित्त आयोग:** वित्त आयोग के कर बंटवारे के मानदंडों पर भी सवाल उठाए गए हैं, जो प्रायः प्रगतिशील राज्यों को नुकसान पहुंचाते हैं।
- केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता:** राज्यों के राजस्व में केंद्रीय हस्तांतरण का योगदान 44% है, कुछ राज्यों में इस पर निर्भरता अधिक है- जैसे- बिहार 72%। इससे तरलता प्रबंधन प्रभावित होता है और केंद्र में सत्तारूढ़ दल के विपक्षी राजनीतिक दल द्वारा शासित राज्यों में राजनीतिक तनाव उत्पन्न हो सकता है।

RBI का स्वर्ण भंडार

चर्चा में क्यों?

- भारत के स्वर्ण भंडार ने पहली बार 100 बिलियन डॉलर मूल्य का आंकड़ा पार किया। विदेशी मुद्रा भंडार पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नवीनतम डेटा के अनुसार, भारत का गोल्ड रिजर्व 102.3 बिलियन डॉलर का हो गया है।

मुख्य बिन्दु:

- इस वजह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण का हिस्सा लगभग 15% हो गया है, जबकि एक दशक पहले यह लगभग 7% था।

RBI का स्वर्ण भंडार क्यों बढ़ रहा है?

- **मुद्रा भंडार में विविधता लाने के लिए:** विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति स्रोत में विविधता लाई जा रही है और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम किया जा रहा है। ये सारे प्रयास डी-डॉलरेराइजेशन की दिशा में कदम हैं।
- **जोखिम को कम करने के लिए:** इससे मुद्रा की विनिमय दर में अस्थिरता और उसकी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार के मूल्य में उतार-चढ़ाव के जोखिम से बचने में मदद मिलेगी।
- **मुद्रास्फीति से निपटने में सहायक:** स्वर्ण भंडार को मुद्रास्फीति की स्थिति में संकट से बचाव के रूप में जमा किया जाता है। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की क्रय शक्ति कम नहीं होती है।
- **सुरक्षित निवेश परिसम्पत्ति होना:** आर्थिक और भू-राजनीतिक संकट के दौरान स्वर्ण को सुरक्षित निवेश माना जाता है, जो वित्तीय संकट की स्थिति में बफर का कार्य करता है।

जोखिम

- **कम तरलता या कम आपूर्ति:** आपूर्ति कम होने से स्वर्ण को नकदी में बदलने की प्रक्रिया धीमी और महंगी होती है।
- **शून्य रिटर्न मिलना:** जमा स्वर्ण पर कोई ब्याज नहीं मिलता वहीं मुद्रा जमा करने पर ब्याज मिलता है।

Daily Current Affairs

Date : 27 October, 2025



- **भंडारण और सुरक्षा की अधिक लागत:** धातु के रूप में स्वर्ण को भंडारित करने के लिए अधिक सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। इससे लागत बढ़ जाती है।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के घटक:

- **विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति (FCA):** ये अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और जापानी येन जैसी मुद्राओं में रखी जाती हैं।

- **RBI के पास स्वर्ण भंडार।**

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पास भंडारण:

- **विशेष आहरण अधिकार (SDR):** यह IMF द्वारा सृजित ब्याज-अर्जन वाली आरक्षित परिसंपत्ति है। यह सदस्य देशों की आरक्षित परिसंपत्ति के पूरक का कार्य करती है।

- **रिजर्व ट्रेन्च पोजीशन (RTP):** यह सदस्य देश के कोटा और IMF के पास उस सदस्य देश की मुद्रा की होल्डिंग के बीच का अंतर है। इसे कठोर शर्तों के बिना निकाला जा सकता है।

--:26:--

रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (REER)

चर्चा में क्यों?

- रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच गया तथा रियल नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (REER) निरंतर अवमूल्यन का संकेत दे रही है।

मुख्य बिन्दु:

REER:

- **परिभाषा:** REER किसी देश की मुद्रा के मूल्य को उसके प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की मुद्राओं के एक बास्केट के सापेक्ष मापता है, और फिर इसे सापेक्ष मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाता है।
- इसे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (NEER) को सापेक्ष उपभोक्ता कीमतों के साथ समायोजित करके प्राप्त किया जाता है।

व्यापारिक प्रभाव:

- उच्च REER होने पर निर्यात महंगा और आयात सस्ता हो जाता है, जिससे किसी देश की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा घटती है।
- कम REER इंगित करती है कि मुद्रा अवमूल्यित (अंडरवैल्यूड) है, जिससे संभावित रूप से निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है।

महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट

राज्य खनन तत्परता सूचकांक (SMRI)

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय खान मंत्रालय ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक जारी किया है।

मुख्य बिन्दु:

- **उद्देश्य:** इस सूचकांक का उद्देश्य देश के खनन क्षेत्र के विकास में राज्यों के सापेक्ष योगदान को मापना, खनन क्षेत्र में सुधारों को प्रोत्साहित करना, और राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है।
- **आधार:** यह सूचकांक कोयला को छोड़कर अन्य खनिजों से संबंधित नीलामी में प्रदर्शन, खनन के शीघ्र परिचालन, खोज पर ज़ोर, और सतत खनन पद्धतियों के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन करता है।
- **वर्गीकरण:** राज्यों को उनके खनिज भंडार के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
- **तीनों श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं:**
 - **A:** मध्य प्रदेश, राजस्थान, और गुजरात
 - **B:** गोवा, उत्तर प्रदेश, और असम
 - **C:** पंजाब, उत्तराखंड, और त्रिपुरा।

स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट्स, 2025

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने पहली 'स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट्स 2025' रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट सार्वजनिक और निजी स्रोतों से वन वित्त-पोषण की वैश्विक स्थिति प्रदान करती है।

मुख्य बिन्दु:

- **वित्तपोषण की कमी:** वर्तमान वित्तपोषण और 2030 तक वैश्विक वन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश के बीच 216 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक अंतर मौजूद है।
- **निवेश:** वनों में वार्षिक निवेश को 2023 के 84 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2030 तक तीन गुना बढ़ाकर 300 बिलियन डॉलर और 2050 तक छह गुना बढ़ाना होगा।
- 2023 में वन वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत सरकारें थीं, जिनका कुल वित्तपोषण में 91% योगदान था।

वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI), 2025



चर्चा में क्यों?

- वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI), 2025 रिपोर्ट जारी की गई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) द्वारा 2010 से हर साल जारी की जाती है।



मुख्य बिन्दु:

- वैश्विक स्तर पर निर्धन आबादी: 109 देशों की 6.3 बिलियन आबादी में से 1.1 बिलियन (18.3%) लोग चरम बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं।
- भारत में बहुआयामी निर्धनता: भारत में यह दर 2005-06 की 55.1% से घटकर 2019-2021 में 16.4% रह गई है। लगभग 414 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।

- कार्यप्रणाली: यह सूचकांक 3 आयामों और 10 संकेतकों पर आधारित है।

प्रमुख संकेतकों के मापदंड

स्वास्थ्य

- पोषण: 70 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, जिसके लिए पोषण संबंधी जानकारी कुपोषित के रूप में उपलब्ध है।
- बाल मृत्यु दर: सर्वेक्षण से पहले के पांच वर्षों की अवधि में सर्वेक्षण वाले घर में 18 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे की मृत्यु हुई हो।

शिक्षा

- स्कूलिंग के वर्ष: घर के किसी भी पात्र सदस्य ने 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की हो।
- स्कूल में उपस्थिति: स्कूल जाने की उम्र का कोई भी बच्चा उस उम्र तक स्कूल नहीं जा रहा है, जिस उम्र में उसे कक्षा 8 पूरी कर लेनी चाहिए थी।
- जीवन स्तर: स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छता, पेयजल आदि तक पहुंच।

वैश्विक वन संसाधन आकलन (GFRA) 2025 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने "वैश्विक वन संसाधन आकलन (GFRA) 2025 रिपोर्ट" जारी की। यह रिपोर्ट प्रत्येक पांच वर्षों में जारी की जाती है। इसे इंडोनेशिया के बाली में ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव (GFOI) प्लेनरी के दौरान प्रकाशित किया गया।

मुख्य बिन्दु:

- GFOI, ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन्स (GEO) का एक प्रमुख कार्यक्रम है। GEO एक ऐसा नेटवर्क है, जिसमें सरकारें, शैक्षणिक संस्थान, संगठन, नागरिक समाज और निजी क्षेत्रक शामिल हैं। इसका उद्देश्य अर्थ इंटेलिजेंस क्षमता का उपयोग करना है।
- भारत GEO का सदस्य है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- **वन क्षेत्र का विस्तार:** वन वैश्विक भू-क्षेत्र के 32% भाग पर फैले हुए हैं।
- विश्व के लगभग आधे वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हैं। इसके बाद बोरियल, समशीतोष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का स्थान आता है। यूरोप में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, जो विश्व के कुल वन क्षेत्र का 25% है।
- **भारत में वन विस्तार:** वैश्विक स्तर पर कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत एक स्थान ऊपर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इस प्रकार भारत में वैश्विक वन क्षेत्र का 2% मौजूद है। रबड़ बागान के मामले में भारत 5वें स्थान पर है।

पुरस्कार

सुंदरबन जलीय कृषि मॉडल

चर्चा में क्यों?

- सुंदरबन जलीय कृषि मॉडल को FAO वैश्विक मान्यता पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैंग्रोव पारिस्थितिकी-तंत्र में संधारणीय जलीय कृषि (SAIME) मॉडल को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) से वैश्विक तकनीकी मान्यता प्राप्त हुई। SAIME मॉडल को नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्डलाइफ सोसायटी द्वारा विकसित किया गया है।

मुख्य बिन्दु:

मैंग्रोव पारिस्थितिकी-तंत्र में संधारणीय जलीय कृषि (SAIME) पहल

- SAIME एक बहु-हितधारक भागीदारी (MSP) पहल है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में मैंग्रोव पारिस्थितिकी-तंत्र का संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु झींगे (shrimp) के व्यापार में रूपांतरणकारी प्रक्रियाओं को मजबूत करना है।
- सुंदरबन में SAIME का लक्ष्य एक मजबूत पारितंत्र बनाना है। इसके तहत खारे जल में जलीय कृषि की एक मानक प्रक्रिया विकसित की जा रही है, जिसमें स्थानीय ब्लैक टाइगर श्रिम्प को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। यह एक समग्र पारितंत्र आधारित दृष्टिकोण है। साथ ही, खारे जल में जलीय कृषि करने वाले किसानों को इस मानक प्रक्रिया में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- **वित्त-पोषण:** इसे ग्लोबल नेचर फंड (GNF) द्वारा नैचरलैंड e.V. और मर्सिडीज बेंज के सहयोग से वित्त-पोषित किया जा रहा है।

--:32:--

Daily Current Affairs

Date : 27 October, 2025



सुंदरबन

- सुंदरबन मैंग्रोव वन बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा में स्थित है।
- यह ज्वारीय जल-मार्गों, पंकयुक्त भूमि और लवणीय दशाओं को सहने में सक्षम मैंग्रोव वनों से समृद्ध छोटे द्वीपों के एक जटिल नेटवर्क से घिरा हुआ है, जो पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं की बेहतरीन मिसाल पेश करता है।
- भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव का क्षेत्र (42.45%) सबसे अधिक है। इसके बाद गुजरात (23.66%) और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (12.39%) का स्थान आता है।
- भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR)-2023 के अनुसार कुल मिलाकर, भारत का कुल मैंग्रोव आवरण 4,991.68 वर्ग किमी है , जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:33:--

वीरता पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने रक्षा कर्मियों के लिए वीरता पुरस्कार प्रशस्तियों को सूचीबद्ध करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है।

मुख्य बिन्दु:

- **उद्देश्य:** ये युद्धकाल और शांतिकाल, दोनों समय बहादुरी, शौर्य या आत्म-बलिदान के कार्यों के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार हैं।
- **पृष्ठभूमि:** पहले तीन वीरता पुरस्कार, परम वीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी, 1950 को स्थापित किए गए थे।
- अशोक चक्र वर्ग प्रथम, अशोक चक्र वर्ग द्वितीय और अशोक चक्र वर्ग तृतीय 1952 में स्थापित किए गए थे।
- जनवरी 1967 में अशोक चक्र वर्ग प्रथम, द्वितीय और तृतीय का नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया।
- इन पुरस्कारों की घोषणा साल में दो बार (गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस) की जाती है।



कॉमनवेल्थ गेम्स (राष्ट्रमंडल खेल)

चर्चा में क्यों?

- अहमदाबाद शहर का नाम 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के शताब्दी संस्करण के आयोजन की मेजबानी के लिए प्रस्तावित किया गया है।

मुख्य बिन्दु:

कॉमनवेल्थ गेम्स:

- पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित हुआ था।
- पिछला कॉमनवेल्थ गेम्स : 2022, बर्मिंघम।
- अगला कॉमनवेल्थ गेम्स: 2026, ग्लासगो।
- मुख्यालय: लंदन
- शासी निकाय: कॉमनवेल्थ स्पोर्ट
- सदस्य: 72 देश
- आयोजन: हर चार साल में एक बार आयोजित